UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Social Work
Research Link - 167, Vol - XVI (12), February - 2018, Page No. 128-130
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

उत्तराखण्ड के हल्द्वानी विकासखण्ड के पाँच गाँवों का समाज कार्य अध्ययन

(मानपुर पश्चिम, तल्ली हल्द्वानी, गौजाजाली बिचली, धौलाखेड़ा और गौजाजाली उत्तर के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र, उत्तराखण्ड के हल्द्वानी विकासखण्ड के पाँच गाँवों के समाज कार्य अध्ययन पर आधारित है। उक्त अध्ययन मानपुर पश्चिम, तल्ली हल्द्वानी, गौजाजाली बिचली, धौलाखेड़ा और गौजाजाली उत्तर, इन पाँच गाँवों के विशेष संदर्भ में अध्ययन किया गया है। 21वीं सदी हमारे देश भारत वर्ष की होगी और इसी क्रम में हमारा देश तेजी के साथ और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण विकास के लिए हमारे देश में अनेक योजनाएँ बनी और आगे भी बनती जाएँगी, परंतु सच्चाई यह है कि आज हमारे देश के गाँवों का अस्तित्व खतरे में पढ़ता सा प्रतीत होता है। जहाँ देश में एक ओर स्मार्ट सिटी जैसे परियोजना पर कार्य हो रहे हैं, वही हमारे देश में सांसद आदर्श ग्राम जैसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सभी सांसद प्रत्येक वर्ष एक गाँव को गोद लेकर उसे आदर्श गाँव के रुप में विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है।

डॉ.नीरजा सिंह

उत्तराखण्ड के तेरह जनपदों में से एक सुप्रसिद्ध नैनीताल जिले का हल्द्वानी विकासखण्ड काठगोदाम से मिलकर हल्द्वानी–काठगोदाम नगर निगम बनाता है। हल्द्वानी उत्तराखण्ड के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों में से है और इसे कुमाऊँ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कुमाउनी भाषा में इसे हल्द्वेणी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हल्दू प्रचुर मात्रा में मिलता था। आज उत्तराखण्ड के गाँव के गाँव पलायन के चलते सूने होते चले जा रहे हैं। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दो वर्ष पूर्व इन सभी गाँवों को गोद लिया गया है, तब से इन गाँवों के लोगों को जो भी इस उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा डिप्लोमा प्रोग्राम में अध्ययन करना चाहता है, उसे यू.ओ.यू. द्वारा शुल्क में लगभग पचास प्रतिशत की छूट दी जाती रही है, और साथ ही इन सभी गाँवों के लोगों के लिए मेडिकल कैंप चलाये जाते रहे हैं, जिसमें सभी ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेते हैं। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय ने गोद लिए हुए गाँवों में हेस्का मॉडल की कुछ कार्ययोजनाओं पर उत्तराखण्ड मक्त विश्वविद्यालय तत्परता से कार्य कर रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य :

(1) उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।

(2) उत्तरदाताओं की स्वास्थ्य दशाओं एवं रोजगार से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना।

(3) रोजगार के प्रति युवाओं की जागरूकता का अध्ययन।

(4) ग्रामीण विकास की योजनाओं का अध्ययन करना।

उक्त अध्ययन की प्रकृति विवरणनात्मक के साथ अन्वेषणात्मक है।

यह शोध अध्ययन विवरणात्मक के साथ अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना पर आधारित है।

इस अध्ययन का समग्र हल्द्वानी ब्लॉक के मानपुर पश्चिम, तल्ली हल्द्वानी, गौजाजाली बिचली, धौलाखेड़ा और गौजाजाली उत्तर गाँव हैं, जिनमें से पचास इकाइयों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन द्वारा किया है।

उत्तरदाताओं का पार्श्वचित्र :

उत्तरदाता की आयु संरचना : वर्गीय स्तर के आधार पर तथ्यों का विवरण यह स्पष्ट करता है कि 26 प्रतिशत उत्तरदाता 20 से 30 वर्ष आयु समूह, 14 प्रतिशत 30 से 40 वर्ष आयु समूह, 30 प्रतिशत 40 से 50 वर्ष आयु समूह, 12 प्रतिशत 50 से 60 वर्ष आयु समूह और 18 प्रतिशत 60 से 70 वर्ष आयु वर्ग समूह की है, स्पष्ट है कि 40 से 50 आयु वर्ग के उत्तरदाता गाँव में सबसे अधिक है।

उत्तरदाताओं की लैंगिक स्थिति : वर्तमान अध्ययन में उत्तरदाताओं के लैंगिक स्थिति स्पष्ट करता है कि 32 प्रतिशत उत्तरदाता महिला एवं 68 प्रतिशत उत्तरदाता पुरुष हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं में महिला एवं पुरुष दोनों ही हैं।

उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति : वर्तमान अध्ययन में उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति का अध्ययन स्पष्ट करता है कि 88 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित हैं और 12 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित हैं। इससे स्पष्ट है होता कि विवाहित उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है।

उत्तरदाताओं के धर्म सम्बन्धी सूचना : तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 90 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू, केवल 10 प्रतिशत उत्तरदाता मुस्लिम हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक

सहायक प्राध्यापक (समाज कार्य विभाग), उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी-नैनीताल (उत्तराखण्ड)

उत्तरदाता हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं।

उत्तरदाता की शिक्षा सम्बन्धी सूचना : वर्गीय स्तर के आधार पर तथ्यों का विवरण स्पष्ट करता है कि परिवार में सबसे अधिक शिक्षित सदस्य का शिक्षा का स्तर प्राइमरी है, अर्थात् सर्वाधिक उत्तरदाता शिक्षित हैं।

उत्तरदाता की आवासीय पृष्ठभूमि की स्थिति : वर्तमान अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं के आवासीय पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हुए विदित होता है कि सबसे अधिक 56 प्रतिशत उत्तरदाता पक्के घर में, 12 प्रतिशत मिश्रित घर में तथा 32 प्रतिशत कच्चे घर में रहते हैं।

परिवार में सदस्यों की संख्या सम्बंधी सूचना : अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि परिवार में सदस्यों की 30 प्रतिशत 4 या 4 से कम सदस्य, 50 प्रतिशत 5 से 7 सदस्य, 16 प्रतिशत 8 से 10 सदस्य तथा 4 प्रतिशत 10 से अधिक सदस्य वर्ग हैं। स्पष्ट है कि सबसे अधिक परिवारों की संख्या 5 से 7 वर्ग समूह की है।

उत्तरदाता की वर्ग की स्थिति : अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं में 60 प्रतिशत सामान्य वर्ग से, 34 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से तथा 6 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति से हैं और अनुसूचित जनजाति से कोई भी उत्तरदाता नहीं है। स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है।

उत्तरदाता की वार्षिक आय सम्बन्धी सूचना : उत्तरदाताओं की वार्षिक आय इस प्रकार है – 100000 से 200000 में 28 प्रतिशत, 200000 से 300000 में 34 प्रतिशत, 300000 से 400000 में 14 प्रतिशत, 400000 से 500000 में 14 प्रतिशत और 500000 से 600000 में 10 प्रतिशत। इससे स्पष्ट है कि सबसे अधिक सम्बंधित आयगत स्तर 100000 से 200000 प्रतिशत है।

उत्तरदाता के पास कृषि योग्य भूमि होने सम्बन्धी सूचना : सारणी के आधार पर विवरण यह स्पष्ट करता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सिर्फ 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास ही कृषि योग्य भूमि मौजूद है और बाकी 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है। स्पष्ट है कि कृषि योग्य भूमिहीन किसानों की संख्या सर्वाधिक है।

उत्तरदाता द्वारा ऋण लेने सम्बन्धी सूचना : तथ्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि कुल 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए ऋण लिया हुआ है, जबकि 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया।

उत्तरदाता के मासिक खर्च सम्बन्धी सूचना : आंकड़ों के अवलोकन से यह विदित होता है कि 32 प्रतिशत उत्तरदाता 5000 से 10000 मासिक रूपये खर्च करते हैं, 18 प्रतिशत उत्तरदाता मासिक 10000 से 15000 रूपये खर्च करते हैं, 22 प्रतिशत उत्तरदाता मासिक से 15000 से 20000 रूपये खर्च करते हैं, 12 प्रतिशत उत्तरदाता मासिक से 20000 से 25000 रूपये खर्च करते हैं और 16 प्रतिशत उत्तरदाता मासिक से 25000 से 30000 रूपये खर्च करते हैं। स्पष्ट है कि 5000 से 10000 मासिक रूपये खर्च करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है।

उत्तरदाता की स्वास्थ्य सुविधा सम्बन्धी सूचना : आंकड़ों के आधार पर 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगता है कि स्वास्थ्य सुविधा का स्तर ठीक है, परन्तु 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वास्थ्य सुविधा का स्तर ठीक नहीं है। यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता स्वास्थ्य सुविधा के स्तर को ठीक और उचित नहीं मानते हैं।

उत्तरदाता को चिकित्सीय सुविधा प्राप्त होने सम्बन्धी सूचना : आंकड़ों के अनुसार मात्र 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ही स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हुईं, जबकि 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं को चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं हुई। स्पष्ट हो जाता है कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में अत्यधिक धन खर्च होने के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति ऐसी है कि लोगों को इसका उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है और सर्वाधिक उत्तरदाताओं को चिकित्सीय सुविधा प्राप्त नहीं हुईं।

प्रतिवेदन :

मूलभूत सुविधायें प्राप्त होने के आधार पर ग्रामीणों की स्थिति सामान्य है, अधिकांशतः ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त हैं एवं प्राप्त आय भी समुचित है। समस्या के नाम पर जो सामने उभर कर आया है, वह है स्वास्थ्य सुविधाएँ, इन सभी गाँवों के निकट प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तो हैं, परन्तु वहाँ पर जिस तरीके की सुविधाएँ मौजूद हैं, उनसे कोई भी ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि न तो इन स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा अस्पतालों में उचित रूप से चिकित्सक मौजूद हैं और न ही लोगों को इन स्वास्थ्य केन्द्रों से लोगों को किसी प्रकार की दवा ही सरकार की ओर से मिलती है।

यदि इन स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो सरकार द्वारा इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर खर्च हो रही भारी भरकम धनराशि औचित्यहीन प्रतीत होती है। यदि लोगों को सही समय पर उचित चिकित्सक की सहायता नहीं मिल पा रही और जरुरत पड़ने पर सरकार की ओर से किसी तरह की दवा लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे सिस्टम का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है।

यही कारण है कि इन ग्रामीणों का सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं से मोह भंग हो चुका है और अपने दम पर प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर उन पर भरोसा जता रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि पैंसे खर्च भी होंगे, तो उचित समय पर सही तरीके से अपना इलाज तो करा पाएंगे। परन्तु स्वास्थ्य सेवाओं की विकट समस्या के चलते लोगों को मजबूरी में जहाँ प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना बढ़ रहा है, वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकारी लाभ ना मिल पाने के कारण सभी ग्रामीणों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है जो चिंता का विषय है।

दूसरी ओर जो समस्या विकट रूप धारण कर रही है, वह है – पलायन। लोग गाँव को छोड़ शहरों की और रुख कर रहे हैं और हल्द्वानी नगर के नजदीक होने के कारण इन गाँवों में लगभग नगर जैसी सुविधाएँ भी मौजूद हैं, परन्तु इन गाँवों के लोग भी रोजगार या नौकरी के लिए तेजी से बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं और अधिकांश घरों में बुजुर्ग निवास कर रहे हैं। बाकी नई पीढ़ी अपने परिवार के साथ बड़े शहरों में बसना पसंद कर रहे हैं, जो कि हमारे समाज और गाँवों की अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है।

अंततः शोध अध्ययन में आँकड़ों का गहन अध्ययन कर जो परिणाम सामने आए हैं, उनके आधार पर यह पता चलता है कि इन गाँवों में पलायन जैसी गंभीर समस्या तेजी के साथ पाँव पसार रही है तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर व्यवस्था के चलते सरकारी स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली का लोगों को लाभ नहीं मिल पाने जैसी गंभीर समस्या सामने उभर कर आयी हैं।

सुझाव एवं संस्तुति :

जहाँ यह उम्मीद की जा रही है कि 21वीं सदी हमारे देश भारत वर्ष की होगी और इसी क्रम में हमारा देश तेजी के साथ और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण विकास के लिए हमारे देश में अनेक योजनाएँ बनी और आगे भी बनते जाएँगी, परन्तु सच्चाई यह है कि आज हमारे देश के गाँवों का अस्तित्व खतरे में पढ़ता सा प्रतीत होता है। जहाँ देश में एक ओर स्मार्ट सिटी जैसे परियोजना पर कार्य हो रहे हैं, वहीं हमारे देश में सांसद आदर्श ग्राम जैसे कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सभी सांसद प्रत्येक वर्ष एक गाँव को गोद लेकर उसे आदर्श गाँव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है।

उपरोक्त शोध अध्ययन के निम्नलिखित सुझाव एवं निष्कर्ष हो सकते हैं –

(1) सरकार ग्रामीणों के जीवन में सुधार लाने के लिए स्पष्ट रणनीति बनाये।

(2) ग्रामीण यदि सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से बंचित हो रहे हैं, तो इस बिंदु को गहराई से लेते हुए इसका तुरंत हल निकालना चाहिए, जिससे लोगों को लाभ मिले।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष चिकित्सालयों का निर्माण हो।

(4) चिकित्सीय सुविधाओं को बड़े महानगरों के तर्ज पर लागू किया जाना चाहिए।

(5) ग्रामीणों को स्वरोजगार हेतु सहयोग किया जाना चाहिए।

(6) गाँवों से हो रहे पलायन को गंभीरता से लेते हुए इस समस्या का हल निकाल कर इस समस्या को खत्म करने के भरसक प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे गाँवों से पलायन रुक सके।

(7) लोगों को गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाना चाहिए।

(8) सभी गाँवों को आदर्श गाँव की तर्ज पर विकसित करने का लक्ष्य तय होना चाहिए और इस पर कार्य भी होना चाहिए।

(9) अभी तक जो भी योजनाएँ ग्रामीण विकास के लिए बनी हैं, उन सभी योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जानी चाहिए।

गाँवों में जैविक खेती को प्रोत्साहन एवं शहरों की तर्ज पर गाँव में भी बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, विद्यालय तथा उन्नत संचार व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए।

सन्दर्भ :

(1) आहूजा, राम एवं आहूजा, मुकेश (2008) : समाजशास्त्र विवेचना एवं परिप्रेक्ष, पृष्ठ 234.

***(2)** दोषी, एस.एल. (2011) : आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक, पृष्ठ 54.*

***(3)** उड़ान, जुलाई–सितम्बर 2016, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, पृष्ठ 02.*

***(4)** डॉ महाजन (2010) : प्रारंभिक समाजशास्त्र, पृष्ठ 332.*

***(5)** महाजन, डॉ संजीव (2010) : भारतीय समाज, पृष्ठ 149.*

***(6)** त्यागी, सुरेन्द्र (2011) : आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, पृष्ठ 113.*

***(7)** पन्त, डॉ. डी.सी. (2011) : भारत में ग्रामीण विकास, पृष्ठ 142.*

❁ ❁

UGC -

APPROVED - JOURNAL

UGC Journal Details

Name of the Journal :	Research Link
ISSN Number :	09731628
e-ISSN Number :	
Source:	UNIV
Subject:	Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a;Social Sciences(all)
Publisher:	Research Link
Country of Publication:	India
Broad Subject Category:	Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science

Print

'रिसर्च लिंक' की सदस्यता का शुल्क भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सीधे ट्रांसफर या जमा किया जा सकता है। बैंक का विवरण निम्नानुसार है-

बैंक : स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

ब्रांच : ओल्ड पलासिया, इन्दौर,

कोड - **SBIN 000 3432**

खाते का नाम : रिसर्च लिंक,

खाता नंबर - **63025612815**

भुगतान की मूल रसीद, शोध-पत्र एवं सीडी के साथ कार्यालयीन पते पर भेजना अनिवार्य है।